vinetur

ब्राज़ील में 16 दिसंबर से कानूनी कार्यसप्ताह 42 घंटे का होगा

संशोधन वेतन और दो सवेतन विश्राम दिवस बरकरार रखता है ; 40 घंटे की सीमा से पहले आतिथ्य कारोबारों को शिफ्ट नए सिरे से तय करनी होंगी

सोमवार, 23 नवंबर 2026



ब्राज़ील में 16 दिसंबर से मानक कानूनी कार्यसप्ताह 44 घंटे से घटाकर 42 घंटे किया जाएगा। इस बदलाव के चलते बार, रेस्तरां और ठहरने की सुविधाएं देने वाले कारोबार लंबे समय तक संचालन और सप्ताहांत की सेवाओं के लिए अपने कार्य-समय में बदलाव करने को मजबूर हो रहे हैं।

यह उपाय संवैधानिक संशोधन 141 के तहत तय किया गया, जिसे ब्राज़ील की राष्ट्रीय कांग्रेस ने 16 अक्टूबर को लागू किया। संशोधन दो सवेतन साप्ताहिक विश्राम दिवसों की गारंटी भी देता है और कहता है कि काम के घंटों में कटौती के साथ वेतन कम नहीं किया जा सकता। दूसरा चरण 16 दिसंबर, 2027 को निर्धारित है, जब सामान्य सीमा फिर घटकर सप्ताह में 40 घंटे रह जाएगी।

यह बदलाव पूरे श्रम बाज़ार पर लागू होता है, लेकिन खाद्य सेवा और आतिथ्य क्षेत्रों में इस पर खास ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि इन कारोबारों में अक्सर बारी-बारी से शिफ्ट, देर रात तक काम और रातों, सप्ताहांतों तथा छुट्टियों में अधिक कर्मचारियों की ज़रूरत होती है। इन क्षेत्रों में साप्ताहिक सीमा में मामूली कटौती भी इस बात को प्रभावित कर सकती है कि प्रबंधक काम के घंटे कैसे बांटते हैं, व्यस्त समय में सेवाएं कैसे संभालते हैं और अतिरिक्त कर्मचारियों की ज़रूरत है या नहीं, यह कैसे तय करते हैं।

पहले चरण में मौजूदा साप्ताहिक अधिकतम सीमा 2 घंटे घटेगी, यानी 44 घंटों से 4.55% की कमी। वेतन जस का तस रहने पर गणना के अनुसार प्रति घंटा वेतन में 4.76% की वृद्धि होगी। इसका यह अर्थ नहीं है कि हर नियोक्ता का कुल वेतन-व्यय या श्रम लागत भी उतनी ही बढ़ेगी। अंतिम असर कर्मचारियों की तैनाती के तरीकों, ओवरटाइम के इस्तेमाल, शिफ्ट के स्वरूप, सामूहिक समझौतों और अतिरिक्त कर्मचारी रखे बिना काम को नए सिरे से व्यवस्थित करने की हर कारोबार की क्षमता पर निर्भर करेगा।

बार और रेस्तरां के लिए मुख्य चुनौती संचालन की है। कई प्रतिष्ठान दोपहर और रात के भोजन, दोनों समय खुले रहते हैं और ऐसी टीमों पर निर्भर करते हैं जो खाना तैयार करने, मेज़ों पर सेवा देने, सफाई और दिन का काम समेटने जैसे कार्यों के बीच काम करती हैं। साप्ताहिक सीमा घटने का मतलब है कि मालिकों और प्रबंधकों को इन ज़िम्मेदारियों का बंटवारा नए सिरे से करना होगा या संचालन के घंटे उतने ही बनाए रखने के लिए कर्मचारी बढ़ाने होंगे। होटलों और अन्य आवासीय कारोबारों के सामने भी ऐसी ही चुनौती है, क्योंकि रिसेप्शन, हाउसकीपिंग, रखरखाव और खाद्य सेवा में अक्सर पूरे दिन अलग-अलग समय पर शिफ्ट चलती हैं।

श्रम संबंधी बदलाव पहले ही मंज़ूर हो चुका है, इसलिए बहस अब कानून बनाने से हटकर उसे लागू करने पर केंद्रित है। Brasil 61 की 21 नवंबर को प्रकाशित रिपोर्ट में कारोबारों के सामने चल रही अनुकूलन प्रक्रिया और दिसंबर में बदलाव लागू होने की तारीख नज़दीक आने के साथ कुछ नियोक्ताओं की अपेक्षित मुश्किलों पर ध्यान दिया गया। क्षेत्र की तात्कालिक चिंता यह नहीं है कि नियम लागू होगा या नहीं, बल्कि यह है कि कारोबार समय रहते कर्मचारियों की योजनाओं में बदलाव कितनी जल्दी कर पाएंगे।

यह संशोधन कार्य-समय के दो बुनियादी पहलुओं को एक साथ बदलता है: साप्ताहिक काम के अधिकतम घंटे और साप्ताहिक विश्राम की व्यवस्था। नियोक्ताओं के लिए इसका मतलब है कि नियम का पालन केवल किसी कर्मचारी के कार्य-समय से 2 घंटे घटाने तक सीमित नहीं है। कंपनियों को वेतन बरकरार रखते हुए यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विश्राम की अवधि नई संवैधानिक शर्तों के अनुसार तय हो। जहां कर्मचारियों का आना-जाना अधिक है या शिफ्ट तय करने के अनौपचारिक तरीके प्रचलित हैं, वहां इसके लिए अधिक औपचारिक शिफ्ट योजना और वेतन-भुगतान पर कड़ी निगरानी की ज़रूरत पड़ सकती है।

इस सुधार से भर्ती और कीमतों पर व्यापक सवाल भी उठते हैं, हालांकि इसके अंतिम प्रभाव अभी अनिश्चित हैं। जो कारोबार अधिक सुव्यवस्थित शेड्यूल के ज़रिये बदलाव को संभाल सकते हैं, उनकी लागत में कम वृद्धि हो सकती है। सेवा के घंटे पूरे करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की ज़रूरत वाले कारोबारों का श्रम-व्यय अधिक बढ़ सकता है। रेस्तरां और बार में, जहां मुनाफे का मार्जिन पहले ही कम हो सकता है और मांग दिन तथा मौसम के अनुसार बदलती रहती है, श्रम व्यवस्था में मामूली बदलाव भी कर्मचारियों की संख्या, मेनू की कीमतों और खुलने के समय को प्रभावित कर सकता है।

अब तक उपलब्ध जानकारी कानूनी समय-सारणी और बुनियादी शर्तें तय करती है, लेकिन रोजगार या उपभोक्ता कीमतों पर अंतिम असर का आकलन नहीं करती। यह संभवत: इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले महीनों में कारोबार कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और क्या वे छोटे कार्यसप्ताह की भरपाई उत्पादकता में बदलाव, नई भर्तियों या ओवरटाइम में कटौती से करते हैं।

ब्राज़ील की कांग्रेस ने देश की संवैधानिक प्रक्रिया के तहत संशोधन को मंज़ूरी दी, जिससे इसे सामान्य वैधानिक बदलाव

की तुलना में अधिक मज़बूत कानूनी आधार मिला। नियोक्ताओं के लिए यह अहम है, क्योंकि इससे नियम के लंबे समय तक बने रहने को लेकर अनिश्चितता घटती है और अल्पावधि में इसे पलटने की गुंजाइश सीमित होती है। कर्मचारियों के लिए संशोधन दो वर्षों में काम के घंटे घटाने का स्पष्ट रास्ता तय करता है और नाममात्र वेतन की रक्षा करता है।

अब सेवा क्षेत्र के सामने इस नीति को व्यवहार में लागू करने की चुनौती है। लंबे समय तक खुले रहने वाले कारोबारों को तय करना होगा कि नई साप्ताहिक सीमा का उल्लंघन किए बिना सेवाएं कैसे जारी रखी जाएं, और उन्हें यह काम 16 दिसंबर को पहला चरण शुरू होने से पहले करना होगा। 16 दिसंबर, 2027 को दूसरी कटौती के बाद कार्यसप्ताह 40 घंटे का हो जाएगा। इसका अर्थ है कि कंपनियां अभी जो बदलाव करेंगी, वे कामकाज के लंबे पुनर्गठन का केवल पहला कदम हो सकते हैं।